

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3447

दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

1962 में चीन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र

3447. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के पास 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान चीन द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों के बारे में कोई आंकड़े हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1962 के बाद से, युद्ध के दौरान गवायें गए ऐसे क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए चीन के साथ कोई कूटनीतिक प्रयास या पहल की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त वार्ता कितनी आगे बढ़ी है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ग) वर्ष 1962 के युद्ध के अंत में, चीन का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा था।

पिछले कुछ वर्षों में लंबित सीमा प्रश्न के समाधान के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय स्तर पर कई पहल की गई हैं।

जून 1981 में चीनी विदेश मंत्री हुआंग हुआ की नई दिल्ली यात्रा के बाद, भारत और चीन ने दिसंबर 1981 से नवंबर 1987 तक सचिव स्तर पर आठ दौर की औपचारिक सीमा वार्ता की।

दिनांक 19-23 दिसंबर 1988 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह के गठन की घोषणा की। वर्ष 1989 और 2005 के बीच संयुक्त कार्य समूहों की कुल 15 दौर की बैठकें हुईं।

प्रधानमंत्री वाजपेयी की 22-27 जून 2003 की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा समझौते की रूपरेखा को समझने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की घोषणा की। विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के पहले पांच दौर के आधार पर दोनों पक्षों ने 11 अप्रैल 2005 को “भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान हेतु राजनीतिक मापदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत संबंधी करार” पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 2012 तक विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 10 दौर की वार्ता हुई, जिसके अंत में दोनों पक्षों ने दिसंबर 2012 में “भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा विवाद के समाधान की रूपरेखा पर वार्ता पर आम सहमति” में सहमति के अन्य तत्वों की पहचान की। तत्पश्चात विशेष प्रतिनिधियों के बातचीत के 8 और दौर आयोजित किए गए हैं, अंतिम दौर की बातचीत बीजिंग में दिनांक 18 दिसंबर 2024 को हुई थी।
